

श्री शक्ति सिंह नाम  
 प्रथम/अभिभाषक व धारितांक 30/10/2013  
 को प्रस्तुत  
 830/30.10.2013

राजस्व दितोय जमीन क्र०:-  
 प्रस्तुति दिनांक :- 30-10-2013

183

*[Signature]*  
 अधीक्षक

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म०१०

अपील - 4604-11-13

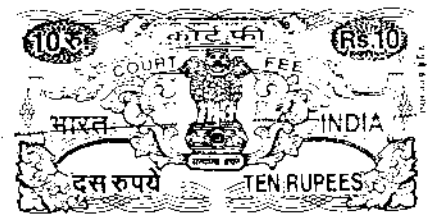
ग्यालियर के सपना

कमिश्नर अदालत  
 9/11/13  
 27/11/13

~~8~~  
 2-12-13

*[Signature]*

- (१) रत्नसिंह पिता श्री सावल जी ठाकुर  
 आयु ७७ वर्ष, धन्या खेती
- (२) प्रेमसिंह पिता श्री सावल जी ठाकुर  
 मृतक का वारिसान :-  
 (अ) श्रीमती पार्वतीबाई पति प्रेमसिंह ठाकुर  
 उम्र ६६ वर्ष, धन्या कृषि  
 (ब) लालनसिंह पिता स्व० प्रेमसिंह ठाकुर  
 उम्र ४२ वर्ष, धन्या कृषि  
 (स) श्रीमती मन्जुबाई पति स्व० सुनैरसिंह ठाकुर  
 उम्र ४१ वर्ष, धन्या कृषि,
- (३) केशरसिंह पिता सावल ठाकुर  
 मृतक का वारिसान :-  
 (अ) श्रीमती रैलमबाई पति स्व० केशरसिंह  
 उम्र ५७ वर्ष, धन्या कृषि व गृह कार्य  
 (ब) श्रीमती नर्मदाबाई पति स्व० केशरसिंह  
 उम्र ५२ वर्ष, धन्या गृह कार्य व कृषि  
 (स) पूनमचन्द पिता स्व० केशरसिंह  
 उम्र ४० वर्ष, धन्या कृषि  
 (द) गोमप्रकाश पिता केशरसिंह  
 उम्र ३२ वर्ष, धन्या कृषि  
 (इ) जितेन्द्र सिंह पिता केशरसिंह  
 उम्र ३० वर्ष, धन्या कृषि  
 नगी निहासी ग्राम रोवासा तहसील  
 व जिला हन्डीर



-२-

(उ) ममताबाई पति वितेन्द्र सिंह  
उम्र २८ वर्षी, धन्या गृह कार्य  
निवासी नागाव धार

----- अपाहायिण्य

विरुद्ध

(१) लक्ष्मीबाई पिता परमानन्द

उम्र ८२ वर्षी, धन्या लेती

(२) गीताबाई पिता रामेश्वर

उम्र ५० वर्षी, धन्या लेती

(३) कंकसिंह पिता परमानन्द

उम्र ५४ वर्षी, धन्या लेती

(४) कंक पिता परमानन्द

उम्र ५२ वर्षी, धन्या लेती

(५) विमल पिता परमानन्द

मृतक लफे वारिसान :-

(अ) मंजुबाईपति विमल

उम्र ४६ वर्षी, धन्या गृह कार्य

(ब) शैलेन्द्र पिता विमल

उम्र २४ वर्षी, धन्या लेती

(स) अजय उर्फ अरुण पिता विमल

उम्र २२ वर्षी, धन्या लेती

सर्वा निवासी ग्राम रंगवाला

तहसील व जिला इन्दौर मध्य०

(६) श्रीमती चन्दाबाई पति श्यामसिंह

उम्र नामालूम, धन्या गृह कार्य

निवासी ३७, कृष्ण करिम नगर,

न्यू देवास भांपाल रोड, देवास मध्य०

(७) श्रीमती सुनाबाई पति बाधूसिंह

उम्र ४८ वर्षी, धन्या गृह कार्य

निवासी शुजातपुर जिला शुजातपुर

निवासी ५०६, राजाराम नगर, देवास

(६) श्रीमान सुरेश जोशी पटवार्णे महोदय  
(रिटायर्ड) म०प्र० शासन

क्लेक्टर कार्यालय मौतोतकोटा, इन्दौर

निवासी ११२, कुमावतपुरा, इन्दौर ---- रैस्यान्हेन्ट्य

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा ४४ उप धारा (२)

म०प्र० मू-राजस्व संहिता १६५६ .

महोदय,


अपीलाधीनता की ओर से निवेदन है कि :-

श्रीमान क्लेक्टर महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक -  
१४४।अ-७४।११-१२ ( रत्नसिंह सोबल व अन्य विरुद्ध लज्जोबाई  
विधवा परमानन्द व अन्य ) में पारित आदेश दिनांक २८-३-२०१३  
से असन्तुष्ट होकर श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर से मांग  
इन्दौर की रा० प्रथम अपील क्रमांक ४१२।अपील।२०१२-१३  
( रत्नसिंह विरुद्ध लज्जोबाई ) में पारित आदेश दिनांक ३०-७-१३  
से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर सदर द्वितीय अपील तथात्फ  
सर्व वैधानिक आधारी सर्व विधि सम्बन्धी प्रश्न पर निम्नानुसार  
प्रस्तुत करते हैं :-

19-6-2014

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30--7--2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि जिला न्यायाधीश, इंदौर के बजावरी प्रकरण क्रमांक 3/77/90 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिवीजन क्रमांक 421/2001 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-10-2010 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष दिया है कि प्रश्नाधीन आदेशों को उचित फोरम में उचित तरीके से चैलेंज करें । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरुस्ती का अधिकार कलेक्टर को है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित फोरम में

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशों के विरुद्ध उचित फोरम में उचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

  
(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष